# अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के वोटर्स ट्रम्प के समर्थन में

## हालांकि हैरिस भारतीय मूल की हैं पर इण्डो अमेरिकन वोटर्स को वे पसंद नहीं हैं

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **इसका कारण यह भी है, कि कमला हैरिस अपने भारतीय मूल के होने का जिक्र करने से प्रायः कतराती हैं और भारतीय मूल के अमेरिकन वोटर्स पर भी प्रायः मौन ही रहती हैं। शायद उन पर, खुद को अमेरिका के प्रति पूर्ण निष्ठावान साबित करने का दबाव है।**
- **चुनावों में जहां बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरह से हैरिस के पक्ष में एक जुट है, वहीं, अश्वेत मतदाता, जो अब तक डैमोक्रेट्स का वोट बैंक था, ट्रम्प के पक्ष में दिख रहा है।**

नई दिल्ली, 5 नवंबर। अमेरिका की जनता मतदान करने जा रही है, ऐसे में एक स्पष्ट निर्णय यह सामने आया है कि अमेरिका के लोग डॉनल्ड ट्रम्प तथा कमला हैरिस के बीच आधे-आधे बंटे हुए हैं।

राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कुछ आश्चर्यजनक बातें भी हुई हैं- पारंपरिक जनाधार बदल रहे हैं और नई वफादारियाँ उभर रही हैं। उदाहरण के लिए, अश्वेत मतदाताओं को लें, वे पारंपरिक रूप से हैरिस की डैमोक्रैटिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मतदान करते थे।

लेकिन, इस बार मतदान ट्रम्प व हैरिस के बीच विभाजित है। इस बार कई अश्वेत मतदाता, डैमोक्रैटिक उम्मीदवार के लिए अपनी पारंपरिक पसंद के बजाय ट्रम्प के पक्ष में हैं।

दूसरी स्पष्ट बात यह है, बुद्धिजीवियों का समर्थन, हैरिस की तरफ इकट्ठा हो गया है और डॉनल्ड ट्रम्प का डटकर विरोध कर रहा है। इन लोगों को हैरिस का समर्थन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने मुख्य रूप से ट्रम्प के प्रति नफरत के कारण ऐसा किया है। इस बार सभी बुद्धिजीवी हैरिस के झण्डे के पीछे एकजुट हो गए हैं।

भय यह है कि यदि ट्रम्प सत्ता में आ गए तो अमेरिकी लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा। वहीं, हैरिस स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगी, जिससे हर क्षेत्र में मतभेद की गुंजाइश बढ़ सकती है।

भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो, आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय मूल के अमरीकी ट्रम्प के पीछे एकजुट हो रहे हैं। भारतीय अमरीकी जनता अब डैमोक्रैटिक पार्टी के मापदंडों के पीछे इकट्ठी नहीं हो रही है। कई भारतीय ट्रम्प के साथ हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं।

भारतीय प्रवासियों को लुभाने के लिए ट्रम्प काफी समय से भारत समर्थक लाइन आगे कर रहे हैं। कुछ ही हफ्ते पहले ट्रम्प ने भारतीयों की कड़ी मेहनत करने की संस्कृति, शिक्षा में विश्वास तथा जन्मजात उद्यम को अमेरिका के लिए "ऐसेट" (संपत्ति) बताया था।

दूसरी तरफ, हैरिस ने हिन्दुओं और उनके उद्यमी गुणों के बारे में चुप्पी साध रखी है। हो सकता है कि हैरिस खुद को एक सच्ची अमेरिकी नागरिक के रूप में प्रोजैक्ट करने की उत्सुक रही हों। उन्होंने बार-बार कैलिफोर्निया में अपने स्कूल के दिनों का जिक्र किया और बताया कि कैसे वो नियमित रूप से बस से स्कूल ट्रिप्स पर जाया करती थीं।

उनकी कहानी मध्यम वर्ग के अमेरिका की है, जो बाद में बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ डॉनल्ड ट्रम्प को अपने पिता से हज़ारों-करोड़ों की संपत्ति विरासत में मिली थी और वे "वाइट सुप्रिमेसी" (श्वेत वर्चस्व) जैसे आंदोलनों में सबसे आगे रहे थे।

अपने कठोर रूढ़िवादी रूख के साथ, डॉनल्ड ट्रम्प एम.ए.जी.ए. (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) मूल्यों की बात कर रहे हैं और इन मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। उधर हैरिस, यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक मित्रों के प्रति अधिक उदार है।

माना जाता है कि हैरिस का चीन के साथ व्यवहार अधिक नरम है, जबकि ट्रम्प चीन को अमेरिका का "नम्बर वन" दुश्मन मानते हैं।

वे चीन के खिलाफ, हैरिस की तुलना में कहीं अधिक कठोर उपायों की बात कर रहे हैं, जैसे कि चीनी वस्तुओं और सेवाओं पर इतना अधिक उच्च स्तर का टैरिफ (शुल्क), जितना कि हैरिस सोच नहीं पातीं।

भारतीय मूल की होने के कारण, हैरिस को अपने अडॉप्टेड होम (दत्तक घर) के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती। अमेरिका के प्रति निष्ठा साबित करना हैरिस के लिए अधिक मुश्किल होगा।

इमिग्रेशन (अप्रवासन) के मुद्दे पर, हैरिस की तुलना में ट्रम्प अधिक सख्त होंगे। हैरिस, संसाधनों को जुटाने तथा अपमानता को कम करने के लिए उच्च आयात की बात करती हैं।

आर्थिक नीति में 'हैरिस, डॉनल्ड ट्रम्प की तुलना में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था एवं एक्शन प्रोग्रामों की अधिक सकारात्मक तस्वीर पेश करती हैं।

## संसद सत्र 25 नवम्बर को शुरू होगा

नयी दिल्ली, 05 नवंबर। सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित कराने की मंगलवार को घोषणा की। इस दौरान 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जायेगा।

- **शीतकालीन सत्र 20 दिसम्बर तक चलेगा।**

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी देते हुये कहा, भारत सरकार की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक आहूत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

संसद की कार्यसूची के अनुसार, शीतकालीन सत्र की अवधि में संशोधन भी किया जा सकता है।

रिजिजू ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान को अंगीकार किये जाने की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में एक समारोह संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किया जायेगा।

# फिर से भाजपा के हिंदुत्व आइकन बने योगी आदित्यनाथ

## योगी का "बटेंगे तो कटेंगे" नारा काफी चर्चित हो रहा है

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- **योगी ने हरियाणा की एक चुनावी सभा में यह नारा दिया था, समझा जाता है कि इससे भाजपा को भारी लाभ हुआ हरियाणा में और अब महाराष्ट्र व झारखंड में भी योगी व उनका यह नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है।**
- **संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और प्रधानमंत्री मोदी तक योगी के इस नारे के प्रशंसक हैं तथा उन्होंने इसका समर्थन किया है।**

नई दिल्ली, 5 नवम्बर। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा में भले ही कमी आ गई थी, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी करते हुए, भाजपा में हिन्दुत्व के प्रतीक के रूप, अपना पूर्व कद फिर से हासिल कर लिया है।

झारखण्ड और महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों के प्रचार में योगी की जबरदस्त मांग हो रही है तथा उनका "बंटेंगे तो कटेंगे" नारा भाजपा के हल्कों में जबरदस्त हिट हो रहा है। मथुरा में 22 अक्टूबर को आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुई उनकी मीटिंग के दो दिन बाद, आर.एस.एस. के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले योगी की इस टिप्पणी को, उनके इस नारे को दोहराया था, जो योगी ने हरियाणा चुनावों में काम लिया था और काफी असरदार रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी योगी के इस नारे का समर्थन किया बताते हैं।

रोचक बात यह है कि लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद, योगी 3 नवम्बर को प्रधानमंत्री से पहली बार मिले थे। इससे पूर्व, गत माह हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई एन.डी.ए. के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में, वे प्रधानमंत्री के श्रोता के रूप में शामिल जरूर हुए थे। उस दिन, योगी ने गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ लम्बी मीटिंग भी की थीं।

लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा की घोर पराजय के बाद के महीनों में, योगी कटघरे में खड़े कर दिये गये थे तथा पार्टी के खोजी लोग यह कहने लगे थे कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा उन्हें पार्टी के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। हाल ही में, आर.एस.एस. और भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ हुई मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग ऐसे संकेत दे रही हैं कि उन्होंने, कम से कम फिलहाल तो, अपने अस्तित्व के संकट पर विजय पा ली है।

योगी ने आज झारखंड में अपना प्रचार-अभियान कर दिया। उन्होंने एक दिन में तीन जनसभाएं संबोधित कीं। हजारी बाग की सभा में उन्होंने अपना नारा दोहराया: "ये समय बंटने का नहीं है। कांग्रेस ने 1947 से देश को बांटा है।" योगी का "बंटेंगे तो कटेंगे" नारे के महाराष्ट्र में भी गूंजने की संभावना है। महाराष्ट्र में योगी की सभाओं की तिथियों एवं स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

### 23 नवम्बर ...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

लायेंगी। इसके परिणामस्वरूप, राहुल और प्रियंका की टीमों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है।

संगठन में बदलाव अपेक्षित भी है तथा जब भी यह बदलाव होगा, उस समय यह देखना बड़ा रुचिकर होगा कि कौनसा नेता किस खेमे से जुड़ा हुआ है।

## अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

हासिल करना होगा। वर्तमान में 50 स्टेट्स हैं इसलिए जीतने के लिए 26 वोटों की जरूरत होगी। बारहवे संशोधन के इस प्रावधान का अमेरिका के इतिहास में सिर्फ एक बार सन् 1800 के चुनावों में इस्तेमाल हुआ था। यह एक दुर्लभ असाधारण घटना है। लेकिन समान मत मिलने की स्थिति से निपटने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

ए.आई. ने चुनाव नतीजे आने के दौरान असंतोष बढ़ने की संभावना बताई। और चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन, मार्च, रैली जैसी घटनाएं हो सकती है। ए.आई. ने तनाव बढ़ने, हिंसा होने की चेतावनी दी। हाल ही में आए ए.बी.सी. न्यूज/इप्सॉस सर्वे के अनुसार सिर्फ 29 प्रतिशत अमेरिकन मानते हैं कि ट्रम्प हार स्वीकार कर लेंगे, इससे आशंका है कि चुनाव नतीजों के बाद हिंसा होगी। इसी के चलते वॉशिंगटन डी.सी. में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। चुनाव देश को एकजुट करने की बजाय देश को बांट रहे हैं और अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। रॉयटर्स ने बताया कि जिन राज्यों में कडा मुकाबला है वहां के अधिकारी अफवाहों, साजिशों की खबरों, धमकियों व हिंसा की आशंका वाली खबरों पर भरोसा कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया डैट्रॉयट और एटलांटा राज्य जिनके लिए ट्रम्प अक्सर फर्जी वोटिंग के दावे करते हैं, वहां अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया की सुरक्षा के उपाय किए हैं। फिलाडेल्थिका में जहां मतगणना होनी है उस जगह की सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड लगाई गई है। डैट्रॉयर और एटलांटा में मतदान केन्द्रों के खिड़की, दरवाजों पर बुलेटप्रूफ कांच लगाए हैं। विस्कोन्सिन में चुनाव कर्मियों को डीएस्केलेशन टैक्नीकस का प्रशिक्षण दिया गया है तथा मतदान केन्द्रों में बच निकलने का रास्ता बनाया। माहौल खराब होने की स्थिति को देखते हुए। एरिजोना, जहां 2020 में चुनाव में फर्जीवाडे के दावे किए गए थे, में प्रशासन झूठी अफवाहों से निपटने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है, खासकर फर्जी वोटर्स की काल्पनिक तस्वीरों से। अन्य राज्यों को भी सुरक्षा को लेकर भारी चिंता है। रॉयटर्स ने बताया कि वॉशिंगटन के गवर्नर ने नैशनल गार्ड यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। यहां कमला हैरिस के भारी अंतर से जीतने की उम्मीद है। यह गत दिनों बैलेट बॉक्स जलाने की खबर आई थी। सी.एन.एन. ने बताया कि नेवाडा और ऑरेगॉन में नैशनल गार्ड यूनिट्स को तैयार रखा गया है।

गार्जियन ने ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ऑरेगॉन व वॉशिंगटन की बैलेट बॉक्स जलाने, पैनसिल्वेनिया में बम की धमकी दिए जाने, सैन एंटोनियों में चुनाव कर्मी व वोटर के बीच हाथा पाई, और एरिज़ोना शेयर में हथियार बन्द आदमी की गिरफ्तारी घटनाएं प्रमुख हैं। उक्त व्यक्ति की साजिश बडे पैमाने पर हिंसा करने की थी।

इन्टरनैशनल क्राईसिस ग्रुप (आई.सी.जी.) ने चेतावनी दी है कि चुनाव सम्बन्धी हिंसा की संभावना बहुत ज्यादा है। बडे पैमाने पर दलगत ध्रुवीकरण होने से नतीजों को अस्तित्व से जोड़ कर देखा जा रहा है। राजनैतिक हिंसा के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। अप्रैल में हुए एन.पी.आर./पी.बी.एस. पोल के अनुसार 20 प्रतिशत अमेरिकन मानते है कि देश को ठीक करने के लिए हिंसा जरूरी है।

# एजुकेशन प्री-समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **आज हो रहे इस प्री-समिट में शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार, डिजिटल तकनीकों का उपयोग तथा निवेश की सम्भावनाओं पर गहन चिन्तन होगा।**

जयपुर, 5 नवंबर। राइज़िंग राजस्थान से पूर्व, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यिमता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में 6 नवंबर को "एजुकेशन प्री-समिट 2024" का आयोजन होगा।

होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, टोंक रोड, जयपुर में होने वाले इस शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे तथा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले एवं खेल, कौशल, योजना एवं उद्यिमता विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शिरकत करेंगे।

समिट का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीकों का उपयोग और निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना है। प्री-समिट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों के मद्देनज़र, कृष्ण कुणाल, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, नीरज के. पवन, शासन सचिव खेल एवं युवा मामले विभाग, डॉ.आरुषी ए. मलिक शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अविचल चतुर्वेदी, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद सहित विभाग के उच्चाधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

### 'यूपी मदरसा ...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

हुए, इससे संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट मदरसा शिक्षा के लिए वैध ढांचा उपलब्ध करा रहा है, जिसमें एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम के अलावा, धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है।

अदालत ने कहा कि मदरसों द्वारा उच्च शिक्षा की डिग्री देना गैर कानूनी है क्योंकि यह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन (यू.जी.सी.) एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि जहां "मदरसा एक्ट राज्य विधायिका की वैधानिक क्षमता के अन्दर है", वहीं अधिनियम में "फाजिल" और "कामिल" के तेहत उच्च शिक्षा की डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है यह यू. जी. सी. एक्ट की धारा 22 के प्रतिकूल है। यू.जी.सी. एक्ट उच्च शिक्षा के मानक एवं स्तर निर्धारित करता है तथा राज्य की विधायिका यू.जी.सी. एक्ट के प्रतिकूल उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर सकती।"

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ, बोर्ड ऐसे नियम बना सकता है, जो यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाएं, अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना, अपेक्षित स्तर की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करेंगी।"

### "जे.एम.एम...

**( प्रथम पृष्ठ का शेष )**

डागा की जनसभाओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सत्तारूढ़ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जे.एम.एम. का वास्तव में अर्थ "जमकर मलाई मारो" है, अन्यथा जे.एम.एम. के नेताओं और उनके पी.ए. ने करोड़ों रुपए कैसे जमा किए होते।

उन्होंने कहा, नया राज्य बनने के बाद से अब तक झारखण्ड में 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनमें से कई जेल गए, जबकि, भाजपा का एक भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। उन्होंने कहा, जे.एम.एम. की डूबती नाव पर कोई नहीं चढ़ना चाहता, और इसीलिए नई सरकार भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. की होगी।

राजनाथ सिंह ने पिछड़े आदिवासियों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात की। उन्होंने कहा, साठ हजार आदिवासी गांवों को विकसित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि आदिवासी, जो राज्य में सबसे ज्यादा थे, उनकी आबादी घटकर 28 प्रतिशत ही कैसे रह गई है।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लंदन के बैंक में 102 टन सोना "गिरवी" रखा था, जिसे मोदी सरकार धनतेरस के बाद वापस ले आई है।

रक्षा मंत्री ने यह घोषणा भी की कि गोगो दीदी योजना से हर महिला को हर महीने ग्यारह तारीख को 2100 रूपए मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं को 500 रूपए में रसोई गैस सिलैण्डर तथा 2 सिलैण्डर मुफ्त मिलेंगे।

# सी.बी.आई. ने छापों में 50 लाख रुपए बरामद किये

- **जिन पर छापे पड़े वे सभी हेमन्त सोरेन के करीबी, पंकज मिश्रा के नज़दीकी सहयोगी हैं।**

रांची, 05 नवंबर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से आठ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सी.बी.आई. ने पंकज मिश्रा के करीबियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर 50 लाख रुपये कैश जब्त किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 3 राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपये नकद, एक किलो सोना और चांदी के कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, साहिबगंज के 11 जगहों पर छापेमारी हुई तो रांची में 3 और कोलकाता और पटना में एक-एक जगह पर रेड किया गया।

पंकज मिश्रा बरहट विधानसभा के विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं। पंकज मिश्रा और कई लोगों के खिलाफ अवैध खनन मामले में सी.बी.आई. ने 2023 में एफ.आई.आर. दर्ज की थी।

# योगेन्द्र पवार को नेतृत्व सौंपने का संकेत दिया शरद पवार ने

## उन्होंने कहा, 30 साल मैंने जिम्मेवारी निभाई, 30 साल अजित को सौंपी, अब 30 साल योगेन्द्र को देने का समय आ गया

- **शरद पवार ने कहा कि मैं 14 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, और कितनी बार लड़ूंगा, कहीं न कहीं तो रूकना ही पड़ेगा।**

मुबंई, 05 नवंबर। महाराष्ट्र में एक तरफ 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं दूसरी तरफ एन.सी.पी. (एस.पी.) के नेता शरद पवार ने अपने भाषण के माध्यम से अलग ही संकेत दिया है। बारामती जिले के सुपा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान अपने संबोधन में शरद पवार ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब बारामती, के लिए विकास के लिए अगले 30 साल की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए अब यूगेंद्र पवार जैसे नए नेतृत्व की जरूरत है। बातों ही बातों में उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि जिस तरह 30 साल पहले मैंने अजित पवार पर बारामती की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब एक बार फिर वक्त आ गया है कि यूगेंद्र पवार अगले 30 साल बारामती का प्रतिनिधित्व करें।

अपने भाषण में शरद पवार ने कहा, मैं लोकसभा में आप लोगों के दम पर चुनकर गया हूं। लेकिन मैंने तय किया अब लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा, 25-30 साल लगातार चुनाव जीतने के बाद नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसलिए 30 साल पहले मैंने यह फैसला किया कि अब मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और यहां की राजनीति पर अब मैं ध्यान नहीं दूंगा और मैंने सारी जिम्मेदारी अजित दादा पवार को सौंप दी थी। बीते 25-30 साल से यह जिम्मेदारी अजित दादा पर है। यानी कि पहले के 30 साल यह जिम्मेदारी मुझपर थी और उसके बाद अगले 30 साल अजित दादा पर थी।

उन्होंने कहा, यही कारण है कि अब अगले 30 साल की व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर यह व्यवस्था करनी है तो फिर लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्या को समझने और नज़रिया होने की जरूरत है। शरद पवार ने कहा कि वह 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और कितनी बार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जाकर तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा।

शरद पवार ने कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन राज्यसभा में जरूर हूं। अभी डेढ़ साल और बाकी हैं। लेकिन इस डेढ़ साल के बाद अब राज्यसभा में जाना है या नहीं, इसका विचार करना पड़ेगा। मैं लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ूंगा और ना ही कोई अन्य इलेक्शन लड़ूंगा। कितनी बार चुनाव लड़ेंगे?

# धारीवाल पर फिर से चलेगा एकल पट्टे का मुकदमा

- **सुप्रीम कोर्ट ने शांति धारीवाल व अधिकारियों को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर हाईकोर्ट को पुनः सुनवाई कर 6 माह में उचित आदेश पारित करने को कहा।**

जयपुर, 5 नवंबर। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत तत्कालीन यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और अदालती कार्रवाई को निरस्त करने के साथ ही. पूर्व आई.ए.एस. जी.एस. संधू सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दी गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश अशोक पाठक की स्पैशल लीव पिटीशन (एस.एल.पी.) पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने हाईकोर्ट को कहा है कि वह प्रकरण की पुनः सुनवाई कर छह माह में उचित आदेश पारित करे।

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि गत अप्रैल माह में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश शपथ पत्र में प्रकरण में कोई आपराधिक मामला नहीं बनने की बात कही थी, लेकिन इस दौरान उनसे सलाह नहीं ली गई। वहीं, अब नया शपथ पत्र पेश कर हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करने की गुहार की गई थी। अति. महाधिवक्ता शर्मा ने बताया कि मामले में ए.सी.बी. ने तीन क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थीं, वे धारीवाल सहित अन्य अधिकारियों से प्रभावित थीं। इन रिपोर्ट में सभी तथ्यों को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में ए.सी.बी. कोर्ट ने दो क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और तीसरी पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। इस दौरान मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने गत जनवरी माह में पूर्व आई.ए.एस. जी.एस. संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को सही माना और धारीवाल के खिलाफ प्रकरण खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आर.टी.आई. कार्यकर्ता अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की थी, जिसमें कहा था कि शिकायतकर्ता से राजीनामे के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता।

मामले के अनुसार, साल 2014 में रामशरण सिंह की ओर से गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में धांधली का आरोप लगाते हुए ए.सी.बी. में शिकायत दी गई थी। ए.सी.बी. ने यू.डी.एच. के तत्कालीन सचिव जी.एस. संधू, जे.डी.ए. ज़ोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी और निष्काम दिवाकर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को आदेश जारी कर ए.सी.बी. में दर्ज एफ.आई.आर. और ए.सी.बी. कोर्ट में चल रही कार्रवाई तक को रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संधू सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ लंबित मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दे दी थी। इन दोनों आदेशों को अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


# सी.बी.आई. ने छापों में 50 लाख रुपए बरामद किये

- **जिन पर छापे पड़े वे सभी हेमन्त सोरेन के करीबी, पंकज मिश्रा के नज़दीकी सहयोगी हैं।**

रांची, 05 नवंबर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से आठ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सी.बी.आई. ने पंकज मिश्रा के करीबियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर 50 लाख रुपये कैश जब्त किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 3 राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपये नकद, एक किलो सोना और चांदी के कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, साहिबगंज के 11 जगहों पर छापेमारी हुई तो रांची में 3 और कोलकाता और पटना में एक-एक जगह पर रेड किया गया।

पंकज मिश्रा बरहट विधानसभा के विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं। पंकज मिश्रा और कई लोगों के खिलाफ अवैध खनन मामले में सी.बी.आई. ने 2023 में एफ.आई.आर. दर्ज की थी।


मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908